

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्॥ ऋ० १/८६/२



Impact Factor
7.523



ISSN : 2395-7115
नवम्बर 2024
Vol.-20, Issue-5(1)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

वैश्वीकरण के दौर में बदलती सामाजिक व्यवस्था



विशेषांक सम्पादक :
डॉ. गीतू खन्ना,
डॉ. अमनदीप कौर

सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग
एडवोकेट

Publisher :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERCE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा Bohal Shodh Manjusha

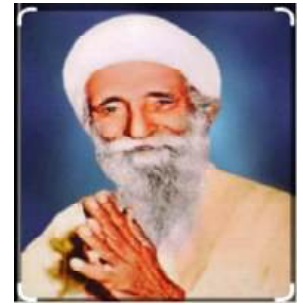
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 20

ISSUE-5(1)

(नवम्बर 2024)

ISSN : 2395-7115



हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, पंचकूला

एवम्

गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर

बहुविषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शोध पत्र

स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERCE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 20

ISSUE-5(1)

(नवम्बर 2024)

ISSN : 2395-7115

प्रेरणा :

चौ. एम. सिहाग

विशेषांक सम्पादक :

डॉ. गीतू खन्ना,

डॉ. अमनदीप कौर

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग 'बोहल', एडवोकेट

एम.ए. (समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता),

एम.फिल (समाजशास्त्र, हिन्दी) एम. लिब., एल-एल.बी. (ऑनर्स),

डिप्लोमा पंचायती राज (रजत पदक विजेता), पी.एच.डी. (हिन्दी)

डी.लिट् (मानद उपाधि), काठमांडू, नेपाल

विभागाध्यक्ष हिन्दी एवं शोध निर्देशक

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर-335001 (राज.)

प्रकाशक :

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी (रजि.)

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा)



Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL REFEREED/REVIEWED AND INDEXED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL
ISSN 2395-7115

सम्पादकीय सम्पर्क :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,

भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : nksihag202@gmail.com

मो. 09466532152

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohal@gmail.com

Facebook.com/bohalshodhmanjusha

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1100/-

- Disclaimer :**
1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
 2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
 3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originality of their views/opinions expressed in their articles.
 4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdiction only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

अनुक्रमिका - नवम्बर 2024

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. गीतू खन्ना, डॉ. अमनदीप कौर	11-11
2.	शुभकामना संदेश		12-15
3.	हिन्दी साहित्य में नारी चित्रण	डॉ. गीतू खन्ना	16-22
4.	वैश्वीकरण के दौर में भारतीय शिक्षा संस्कृति और साहित्य	डॉ. शक्ति बुद्धिराजा	23-27
5.	वैश्वीकरण के दौर में साहित्य में चित्रित परिवर्तित होता पारिवारिक ढांचा	डॉ. अंजू बाला	28-35
6.	वैश्वीकरण का अवधारणात्मक विकास व महिला सशक्तिकरण	संदीप कौर	36-39
7.	वैश्वीकरण के दौर में विखंडित होते जीवन और मानवीय मूल्य : हिन्दी उपन्यासों के संदर्भ में	डॉ. अमनदीप कौर	40-45
8.	वैश्वीकरण के दौर में साहित्य में वर्णित वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था	मिस दीपमाला	46-50
9.	वैश्वीकरणसमये वेदनिहितसामाजिकसिद्धान्तविचारः	अजित कुमार नायक	51-54
10.	साहित्य में वैश्वीकरण का प्रभाव : शरद जोशी और रवींद्रनाथ त्यागी के व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण का विश्लेषण	अर्चना बारस्कर	55-60
11.	वैश्वीकरण के दौर में विखण्डित होते जीवन मूल्य 'गिलिगडु' उपन्यास के संदर्भ में	बीना मीणा	61-64
12.	वैश्वीकरण के दौर में दिविक रमेश के बाल कथा साहित्य में चित्रित बाल समस्याएं	दीपिका चौहान, डॉ. रीता सिंह	65-69
13.	वैश्वीकरण के दौर में साहित्य में वर्णित वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था	धीरेंद्र प्रताप सिंह गौर	70-76
14.	The Impact of Technology on Mental Health of Young Adults : A Systematic Review	Ms. Divya Rathi, Dr. Nirupma Saini, Dr. Vandana Singh	77-84
15.	वैश्वीकरण के दौर में साहित्य में वर्णित वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था	डॉ आदित्य प्रकाश	85-89
16.	वैश्वीकरण के दौर में साहित्य में वर्णित वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था	डॉ. अमिता रेड्डू	90-97
17.	भूमण्डलीकरण और हिन्दी भाषा	डॉ० चन्द्रा खत्री, डॉ० आशा हर्बोला	98-100



वैश्वीकरण के दौर में साहित्य में वर्णित वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था

डॉ. अमिता रेड्ड

सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, गुरु नानक गल्स कॉलेज, यमुनानगर।

वैश्वीकरण ने दुनिया के सभी पहलुओं को गहराई से प्रभावित किया है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था भी एक प्रमुख हिस्सा है। 21वीं सदी में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन मुख्य रूप से वैश्वीकरण की वजह से हुआ है, जहां विभिन्न देशों की शिक्षा नीतियों और प्रणालियों में आपसी तालमेल देखा गया है। भारत भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा है। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव देखे गए हैं, वे मुख्य रूप से तकनीकी विकास, शिक्षा का व्यवसायीकरण, वैश्विक मानकों की आवश्यकता, और समावेशिता पर केंद्रित हैं। साहित्य में इन मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है, जहां लेखकों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की खामियों और उसके सुधार की संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। साहित्य न केवल शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन का साधन है, बल्कि वह एक मार्गदर्शक भी है जो शिक्षा को अधिक सुसंगत, प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए सुझाव देता है।

वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें देशों के बीच की सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं और आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में आपसी निर्भरता और सहभागिता बढ़ती है। यह अवधारणा 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरकर सामने आई, जब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। वैश्वीकरण ने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव डाले हैं। एक तरफ, यह नए अवसर, तकनीकी प्रगति, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए छात्रों को तैयार कर रहा है। वहीं, दूसरी तरफ, यह शिक्षा के व्यवसायीकरण, असमानता और नैतिक मूल्यों के ह्रास की चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर रहा है।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :-

भारतीय शिक्षा व्यवस्था का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविध है, जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है। यह प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलावों से प्रभावित रहा है। इस खंड में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के तीन मुख्य कालखंडों का विश्लेषण किया जाएगा: प्राचीन, मध्यकालीन और औपनिवेशिक काल।

प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था :-

प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था का सबसे प्रमुख उदाहरण गुरुकुल प्रणाली है। इस प्रणाली में छात्र अपने गुरु के आश्रम में रहकर विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे, जिसमें वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित, चिकित्सा,

और खगोल विज्ञान जैसे विषय शामिल होते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं था, बल्कि जीवन के उच्च मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा देना भी था। इस समय शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, और यह मुख्य रूप से समाज के उच्च वर्गों तक ही सीमित थी।

बौद्ध काल में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने विश्व भर से विद्यार्थियों को आकर्षित किया। इन संस्थानों ने विज्ञान, साहित्य, धर्म, और चिकित्सा विज्ञान में गहन अध्ययन को बढ़ावा दिया।

मध्यकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था :-

मध्यकालीन काल में भारतीय शिक्षा पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव पड़ा। इस दौरान मदरसा प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें इस्लामी धर्मशास्त्र, साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान पर ध्यान दिया गया। मदरसों में शिक्षा अरबी और फारसी भाषा के माध्यम से दी जाती थी। इस काल में धार्मिक शिक्षा पर अधिक जोर था, लेकिन साथ ही व्यावहारिक विषयों जैसे चिकित्सा और गणित की भी पढ़ाई होती थी। इस काल में शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक संस्थानों तक सीमित थी और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त नहीं थे। विशेषकर महिलाओं और निचले सामाजिक वर्गों के लिए शिक्षा की पहुंच सीमित थी।

औपनिवेशिक काल :-

भारत की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा परिवर्तन औपनिवेशिक काल में आया। ब्रिटिश शासन ने शिक्षा को औपचारिक रूप दिया और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को लागू किया। 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी गई और पश्चिमी ज्ञान को भारतीय शिक्षा का आधार बनाया गया। इस नीति का उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश शासन के लिए 'निम्नस्तरीय नौकर' तैयार करना था।

औपनिवेशिक काल में भारत में कई विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए गए, जिनमें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय प्रमुख थे। हालांकि, यह शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित थी और व्यापक जनसंख्या को इससे वंचित रखा गया था। शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और वैचारिक विकास से अधिक, प्रशासनिक और तकनीकी कौशल का विकास करना हो गया।

औपनिवेशिक शिक्षा नीति का प्रभाव स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। स्वतंत्र भारत ने अपनी शिक्षा प्रणाली को पुनर्संगठित करने के कई प्रयास किए, जिनमें राधाकृष्णन आयोग (1948) और कोठारी आयोग (1964) जैसे सुधारात्मक प्रयास शामिल थे। परंतु वैश्वीकरण के आगमन से पहले भारतीय शिक्षा प्रणाली अब भी पारंपरिक मूल्यों और औपनिवेशिक ढांचे के बीच झूल रही थी।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, खासकर शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता और साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए। वैश्वीकरण के दौर में इन आवश्यकताओं के चलते बड़े पैमाने पर बदलाव आए, जिसका विश्लेषण हम अगले खंड में करेंगे।

वैश्वीकरण के संदर्भ में वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था :-

वैश्वीकरण ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला है, जिसमें शिक्षा के हर पहलू—शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता, व्यावसायीकरण, और तकनीकी विकास—पर परिवर्तन देखा गया है। वैश्वीकरण के चलते शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत में तकनीकी और

उच्च शिक्षा संस्थानों ने अपनी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वैश्विक शिक्षा मानकों का अनुसरण किया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIMs), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) और अन्य प्रमुख संस्थान अब वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में नवीनतम शिक्षण पद्धतियों, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, और विदेशी सहयोग के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, ऑनलाइन शिक्षा और ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को सुलभ और व्यापक बनाने में मदद की है।

वैश्वीकरण ने शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा दिया है। शिक्षा अब केवल अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ हो रही है। सरकारी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से आरटीई अधिनियम ने सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाया है। हालांकि, अभी भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के बीच असमानता, और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता का लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्राप्त हों।

वैश्वीकरण ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया है। शिक्षा अब एक व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा है, जहाँ निजी संस्थानों की संख्या में वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों का विस्तार हुआ है, जो वैश्विक मानकों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का दावा करते हैं। हालांकि, शिक्षा के व्यावसायीकरण के कारण शिक्षा की पहुँच केवल आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक सीमित हो गई है। सरकारी संस्थानों की शिक्षा का स्तर भी प्रभावित हुआ है, और आर्थिक असमानता के कारण सभी छात्रों को समान शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। शिक्षा का निजीकरण एक दोधारी तलवार की तरह है, जहाँ एक तरफ गुणवत्ता में सुधार होता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा की लागत बढ़ने से यह आम लोगों के लिए दूर होती जा रही है।

वैश्वीकरण के साथ तकनीकी प्रगति का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। डिजिटल शिक्षा, ई-लर्निंग, और स्मार्ट कक्षाएँ शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा दे रही हैं। स्वयं (SWAYAM) जैसे ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म ने उच्च शिक्षा को इंटरनेट के माध्यम से सभी के लिए सुलभ बना दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को भी महसूस किया गया।

तकनीक ने न केवल शिक्षा के वितरण को आसान बनाया है, बल्कि शिक्षा को अधिक इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता केंद्रित बनाया है। इससे छात्रों को वैश्विक शिक्षा सामग्री तक पहुँच मिली है और वे अपने कौशल और ज्ञान को विकसित करने में अधिक सक्षम हुए हैं।

साहित्य में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना :-

भारतीय साहित्य में शिक्षा व्यवस्था की आलोचना एक महत्वपूर्ण और व्यापक विषय रहा है। अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में शिक्षा के पारंपरिक ढाँचे, उसकी खामियों और वैश्वीकरण के प्रभावों का गहन विश्लेषण किया है। साहित्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर विचार-विमर्श न केवल शिक्षा प्रणाली की नीतियों और संरचनाओं की आलोचना करता है, बल्कि यह शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को भी पुनर्परिभाषित करने का प्रयास करता है।

प्रेमचंद की रचनाएँ भारतीय समाज और शिक्षा व्यवस्था की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उनकी रचना

निर्मला में शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भारतीय समाज में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति का वर्णन मिलता है। प्रेमचंद ने समाज में व्याप्त असमानता, पारंपरिक दृष्टिकोण और महिलाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता को बड़े ही सशक्त तरीके से उभारा है। उनके लेखन में स्पष्ट रूप से यह संदेश है कि शिक्षा केवल साक्षरता का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में समता और न्याय स्थापित करना भी है।

रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने उपन्यास गोरा में शिक्षा के औपनिवेशिक प्रभावों और भारतीय समाज में शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। उनका मानना था कि ब्रिटिश शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली के साथ असंगत थी। ठाकुर ने औपनिवेशिक शिक्षा नीति को एकतरफा, व्यावहारिकता से वंचित और मूलतः विदेशी सभ्यता की थोपन के रूप में देखा। उनके साहित्य में शिक्षा का मूल उद्देश्य भारतीय चेतना और सभ्यता को पुनः जागृत करना था।

आधुनिक साहित्य में, चेतन भगत ने द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जैसे उपन्यासों में शिक्षा के व्यावसायीकरण और उसमें बढ़ती प्रतिस्पर्धा की आलोचना की है। उनके उपन्यासों में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि किस प्रकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था अब विद्यार्थियों को सिर्फ रोजगार उन्मुख दृष्टिकोण से तैयार कर रही है, जिससे शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य कहीं खो जाता है। इसमें शिक्षा के मानवीय और नैतिक पहलुओं की कमी की ओर इशारा किया गया है।

इन रचनाओं में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख खामियों जैसे अनुशासन की कठोरता, व्यावसायीकरण, सामाजिक असमानता और स्त्री शिक्षा की उपेक्षा पर गहरी आलोचना की गई है। यह साहित्यिक रचनाएँ केवल आलोचना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए एक आधार प्रदान करती हैं।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए साहित्यिक सुझाव :-

साहित्यकारों ने न केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की है, बल्कि अपने लेखन में सुधार के उपाय भी सुझाए हैं। उनका उद्देश्य केवल व्यवस्था की खामियों की ओर इशारा करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे शिक्षा तंत्र की कल्पना करना था जो अधिक समावेशी, नैतिक, और व्यावहारिक हो। इन साहित्यिक सुझावों ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें पाठ्यक्रम में सुधार, समावेशिता, और शिक्षकों की भूमिका शामिल है।

रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने जीवन में 'शांति निकेतन' की स्थापना करके शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। उनके अनुसार शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्रों को प्रकृति के साथ जोड़कर समग्र विकास पर जोर देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा में अनुशासन की कठोरता को नकारते हुए इसे रचनात्मक, खुला और मानवतावादी दृष्टिकोण से देखने का सुझाव दिया। साहित्य में ठाकुर ने शिक्षा को एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है, जो व्यक्ति के बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास में सहायता करती है।

प्रेमचंद की रचनाएँ हमेशा से नैतिकता और सामाजिक चेतना पर केंद्रित रही हैं। उनकी कहानियों में यह संदेश छिपा होता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यावसायिक योग्यता अर्जित करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में नैतिकता और सामाजिक न्याय की स्थापना करना होना चाहिए। कफन जैसी रचनाओं में उन्होंने शिक्षा

को अधिक नैतिक और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा 'अग्नि की उड़ान' में शिक्षा व्यवस्था में व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका मानना था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाना चाहिए कि छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान न प्राप्त करें, बल्कि उन्हें व्यावहारिक कौशल और अनुसंधान-आधारित शिक्षा प्राप्त हो। कलाम ने एक ऐसे शिक्षा तंत्र की कल्पना की, जो देश की प्रगति में योगदान दे सके और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाए।

महात्मा गांधी ने शिक्षा के माध्यम से आत्म निर्भरता और शारीरिक श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया। उनकी नई तालीम का सिद्धांत यह था कि शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्रों को शारीरिक श्रम से भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को सादा और स्थानीय संदर्भों से जुड़ा बनाने का सुझाव दिया, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग समान रूप से लाभान्वित हो सकें। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देना होना चाहिए।

विभिन्न लेखकों ने शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। उदाहरण के लिए, चेतन भगत जैसे लेखकों ने अपने उपन्यासों में शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने और इसे रोजगारोन्मुखी दृष्टिकोण से मुक्त करने का सुझाव दिया है। उनके अनुसार, शिक्षा को नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, जहाँ व्यक्ति का समग्र विकास हो सके।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ :-

भारत की शिक्षा व्यवस्था, अपने विशाल और विविधतापूर्ण परिदृश्य के कारण, कई चुनौतियों का सामना कर रही है। वैश्वीकरण के प्रभाव के साथ-साथ, देश की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ भी इन चुनौतियों को बढ़ा रही हैं। इन प्रमुख चुनौतियों में क्षेत्रीय असमानता, शहरी और ग्रामीण शिक्षा में अंतर, शिक्षा का निजीकरण, गुणवत्ता में कमी, और कौशल विकास की कमी शामिल हैं।

भारत में शिक्षा की पहुँच में क्षेत्रीय असमानताएँ एक बड़ी चुनौती हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा के स्तर में काफी अंतर है। विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। शहरी क्षेत्रों में अच्छे स्कूल, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक और संसाधनों की उपलब्धता अधिक है, जबकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बड़ी समस्या है। यह क्षेत्रीय असमानता विद्यार्थियों के बीच अवसरों की समानता में बाधा उत्पन्न करती है और शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने में रुकावट डालती है।

शहरी और ग्रामीण शिक्षा में भारी अंतर है। शहरी क्षेत्रों में निजी स्कूलों और अच्छे सरकारी स्कूलों की उपलब्धता के कारण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की बुनियादी संरचना, योग्य शिक्षकों की कमी, और शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के कारण शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। सरकारी योजनाओं जैसे मिड-डे मील और सरव शिक्षा अभियान के बावजूद ग्रामीण भारत में शिक्षा का स्तर शहरी क्षेत्रों से पीछे है। इसके परिणामस्वरूप शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच रोजगार के अवसरों में असमानता बढ़ती जा रही है।

वैश्वीकरण के दौर में भारत में शिक्षा के निजीकरण में तेजी आई है। निजी स्कूल और विश्वविद्यालय अब

शिक्षा का एक प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। निजी स्कूलों में उच्च शुल्क और बेहतर सुविधाएँ होती हैं, जबकि सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। निजीकरण ने शिक्षा को अधिक प्रतिस्पर्धी और परिणाम-केंद्रित बना दिया है, लेकिन इसने सामाजिक असमानता को भी बढ़ाया है, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग महंगी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। इसने शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को और बढ़ाया है, जहाँ केवल आर्थिक रूप से सक्षम लोग ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक अन्य बड़ी चुनौती शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है। स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम तो निर्धारित हैं, परंतु इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की गुणवत्ता अक्सर कमजोर होती है। कई स्कूलों में शिक्षक या तो अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं या पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से नहीं सिखा पाते। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति भी एक बड़ी समस्या है। उच्च शिक्षा में भी गुणवत्ता का अभाव देखा जा सकता है। अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग में पीछे हैं, और यहाँ अनुसंधान और नवाचार पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। यह स्थिति शिक्षा के अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को कमजोर करती है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख दोष यह है कि यह विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल से वंचित करती है। अधिकांश शिक्षा प्रणाली अब भी सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित है, जबकि कौशल विकास और व्यावहारिक प्रशिक्षण को नजरअंदाज किया जाता है। इसका परिणाम यह है कि स्नातक होने के बाद भी कई छात्र उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं होते हैं। यह कौशल अंतर छात्रों को नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ बनाता है और बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाता है।

शिक्षक किसी भी शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ होते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकतर शिक्षक अपने विषय में तो निपुण होते हैं, लेकिन नई शिक्षण विधियों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में पीछे रह जाते हैं। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आती है। इसके अलावा, शिक्षकों की अनुपस्थिति, कार्यभार की अधिकता और वेतन के मुद्दे भी इस समस्या को और बढ़ाते हैं।

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 :-

भारत के शिक्षा क्षेत्र में वैश्वीकरण के संदर्भ में नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 एक ऐतिहासिक कदम है। यह नीति 34 वर्षों बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में लाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप ढालना है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, बहुआयामी और व्यावहारिक बनाना है। इस नीति के प्रमुख बिंदुओं में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न सुधार शामिल हैं, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं।

नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाउंडेशनल स्टेज पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह नीति बच्चों की बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल और गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति को अपनाने पर जोर देती है। इसमें 5+3+3+4 की शिक्षा संरचना को अपनाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और बाल शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण

को बढ़ावा देती है।

नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है। यह कदम शिक्षा को अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि छात्र अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने परिवेश की भाषा में प्राप्त करें, ताकि उनका बौद्धिक और रचनात्मक विकास बेहतर ढंग से हो सके।

नई शिक्षा नीति के तहत, उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और व्यापक बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इसमें अंतरविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिससे छात्र अपने रुचि और करियर के अनुसार विषयों का चयन कर सकें। इसके साथ ही, विश्वविद्यालयों में क्रेडिट बैंक सिस्टम और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है, जिससे छात्रों को अपनी शिक्षा में अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन प्राप्त हो सके।

नई शिक्षा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल से लैस करना है। इस नीति के अंतर्गत, स्कूली शिक्षा से ही छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे नौकरी बाजार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। नीति में स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि भारत की युवाशक्ति वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी भूमिका निभा सके।

नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। डिजिटल शिक्षा ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। नई शिक्षा नीति ने इस पहलू को ध्यान में रखते हुए ई-लर्निंग को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री प्राप्त हो सके।

शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें टीचर ट्रेनिंग को अधिक सख्त और प्रभावी बनाया गया है। नीति के अंतर्गत, शिक्षकों को नए शैक्षणिक पद्धतियों, प्रौद्योगिकी और नवाचारों से सुसज्जित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और गुणवत्ता केंद्रित बनाया जाएगा।

उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास की गुणवत्ता को बढ़ाना और इसे भारतीय शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाना है। यह वैश्विक स्तर पर अनुसंधान में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण, छात्रों के लिए वैश्विक अवसरों की सुलभता, और भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की ओर अग्रसर है। यह नीति शिक्षा के हर स्तर पर समावेशिता, गुणवत्ता और कौशल विकास पर जोर देती है, जिससे भारत वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान बना सके।

वैश्वीकरण ने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर व्यापक प्रभाव डाला है, जिससे न केवल इसकी संरचना बदली

है, बल्कि इसके उद्देश्य और शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन आया है। इस दौरान, साहित्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें लेखकों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्वीकरण के प्रभावों से पूरी तरह लाभ उठाने के लिए इसे और अधिक समावेशी, नैतिक, और रचनात्मक बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समाज में नैतिकता, समता, और न्याय को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। इसके लिए, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है दृ प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, ताकि भारत वैश्विक शिक्षा क्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत कर सके।

अंततः, साहित्य और नई शिक्षा नीति 2020, दोनों ही भारतीय शिक्षा प्रणाली के भविष्य को अधिक समावेशी, प्रभावी, और वैश्विक बनाने की दिशा में मार्गदर्शक हैं। इन सुधारों के माध्यम से, भारतीय शिक्षा प्रणाली वैश्विक मानकों पर खरा उतर सकती है और शिक्षा के माध्यम से समाज के समग्र विकास में योगदान दे सकती है।

संदर्भ :-

1. प्रेमचंद, मुंशी, निर्मला, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. रवींद्रनाथ ठाकुर, गोरा, विश्व भारती प्रकाशन, शांति निकेतन।
3. चेतन भगत, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ़ माई लाइफ़, रूपा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर, हार्पर कॉलिन्स, नई दिल्ली।
5. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, अग्नि की उड़ान (Wings of Fire), यूनिवर्सिटीज प्रेस, हैदराबाद।
6. महात्मा गांधी, नई तालीम (Basic Education), नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय।